रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 995] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2009/आषाढ़ 9, 1931
No. 995] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2009/ASADHA 9, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2009

का.आ. 1592(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 65) किसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 के अधीन जारी की गई पहले अधिसूचना के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.1385(अ), दिनांक 10 अगस्त, 2005 द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 के 407.100 कि.मी. से 456.100 कि.मी. (अमृतसर-अमृतसर सेक्शन) खण्ड के खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और, उक्त अधिसूचना की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 के 407.100 कि.मी. (जालंधर) (सोनेवाल सेक्शन 407.000 कि.मी. से 455.700 कि.मी. (अमृतसर) (सोनेवाल सेक्शन 455.700 कि.मी.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है) खण्ड के विस्तारण की और चार-लेन की सड़क बनाने, विकास, रखरखाव और अनुरक्षण के लिए मैसर्स जालंधर-अमृतसर टोलवे लिमिटेड (प्रस्तावित कंपनी) सी-2, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017 को है (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतधारी कहा गया है) के साथ करार किया है;

और, उक्त रियायत समझौते, रियायतधारी (उपदान राशियां) नियम, 1997 के नियम 4 के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा दिये गए संदाय का प्रतिषेध) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 और 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संदाय के निर्माण, अनुरक्षण, प्रचालन और रखरखाव में कुशलतापूर्वक प्रबंध, निर्माण की गई पूंजी पर आय, पुनर्भुगतान प्रत्याभूति, बकाया की मात्रा और प्राधिकरण और रियायतधारी के बीच किए गए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए यह अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के रखरखाव के लिए शीर्ष की मात्रा के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के प्रकाश में उसके साथ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कोष की मात्रा उक्त खण्ड के कालों और उक्त रियायतधारी को पर्याप्त रूप से प्रदान करने के प्रयोजन से प्रकाशन की तारीख से इसमें से के बाद वर्णित, उक्त करार में यथापरिभाषित शर्तों के तहत कोष समुद्रित और प्रत्याहृत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

टोलवे

पंजाब का खण्ड 410.140 कि.मी. और 455.700 कि.मी. पर स्थित प्रत्याहरणों पर किया जाएगा :

क्रम सं०	पात्र का प्रवर्ग	प्रत्येक एक ओर की पात्र के लिए प्रति कार (शून्य किलो आधार पर पर शीर्ष)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप या अथवा कोच	0.40
2.	भारी वाणिज्यिक यान	0.70
3.	ट्रक, बस	1.40

(1)	(2)	(3)	
4.	बहुपत्नीत्व [धारा 2 (घ) देखिए]	3 वर्ष	5
5.	अपराधपूर्ण लापरवाही और गैर-इरादतन हत्या	3 वर्ष	

टिप्पणी :

1. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "भारतीय न्याय संहिता" से उक्त संहिता के उपबंधों के निम्नलिखित के आधार पर प्रभावित वैवाहिक संबंध अभिप्रेत है;

(क) उक्त संहिता की सम्मति का आशय; और

(ख) उपयुक्त मामलों में व्यक्तिगत अथवा पक्षकार या पक्षकारों और जो एक दूसरे से विलग पृथक्कृत हुए हैं ।

(ii) "कर्तव्यपरायण न्यायालय की सलाह" से वह सलाह अभिप्रेत है जिसमें उक्त संहिता पर सांविधिक उपबंधों, अधिकरण और विधिव्यवसायी के बीच किए गए करार के उपबंधों के अनुसार उक्त संबंध के पुनः होने पर उपबंध प्रभावों द्वारा बंधनकारी, पूर्वतः प्रभावशून्य अथवा अवैध पूर्वतः प्रभावशून्य, आदि किए बने के पश्चात् प्रदत्त होता है ।

(iii) "व्यक्तिगत विधि प्रणाली" से पूर्व विवाह वाले (आदि मामले में पति या पत्नी) अभिप्रेत है, और सम्मिलित है जो ऐसे अधिकारिता विषयक्षेत्रों के भाग सम्मिलीकृत हैं जो मामला लगता ऐसे प्रकार के विवाह करता हो या कार्य करता हो और अपने-अपने उक्त संबंधों के प्रयोजन एवं भाग का उपयोग करते पुष्टिकरण के संबंध है और जिसके लिए विवाह एक प्रकरण प्रकार को पूर्व मानता पड़ता है और इसलिए ऐसी कार्रवाई । अपने कार्यालय या निवास के लिए । या अपने के स्थान । अनुक्रम में पूर्वतः संबंध के किसी पुष्टिकरण करने के लिए ऐसे मामले के उपयोग करना आता है ।

(iv) "व्यक्तिगत कार्यालय न्यायालय" से ऐसा कार्यालय अभिप्रेत है, जिसमें [illegible] एक या दोनों पक्षों के लिए [illegible] है जो मामले और संबंधों को [illegible] में रखते हैं, जो उक्त संबंधों पर एक से अधिक विभिन्न न्यायालयों को पर विवाह विलग होने के लिए विधिमान्य हो में मान्य सीमाएँ हैं ।

(v) "अधिनियम की अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जब अधिकरण और विधिव्यवसायी के बीच किए गए उक्त करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्त की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है ।

(vi) उक्त उपबंधों और धारा 5 का या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "विवाह" में संबंध पति को विवाह अवधि अभिप्रेत है ।

2. निम्नलिखित प्रकार के मामले के अलावा में कोई डिक्री अधिनियम के अनुसार नहीं की जाएगी, अर्थात्,—

(i) पहले वाद,—

(क) जो "अवैध अनुसूची व्यक्ति" प्रतीक करते हैं या व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित के हैं :—

(ख) भारत के राष्ट्रपति;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

(ग) संघ के मंत्रिमंडल या राज्य राज्य मंत्री के मंत्रिमंडल;

(घ) भारत के राज्यपाल और या उनके पदाधिकारी;

(ङ) "सी सी" या "सी सी" नाम वाली अपनी कार्य का उपयोग करने वाला भारत में या से विदेशी नागरिक;

(च) संघ राज्य के मंत्रिमंडल या संघ राज्य के अध्यक्ष या पदाधिकारी, विधान परिषद या संघ विधान राज्य के अध्यक्ष या सभापति, उपाध्यक्ष या उपसभापति, संसद या राज्य या संघ राज्य या संघ विधान सभाओं के विधान के बीच किसी सौहार्द्य के लिए मंत्री की है, और वे संघ या राज्य में मंत्री हों; या

(छ) अनुसूची दस में संशोधन अधिनियम, या अन्य संघ, किसी संघ की, किसी राज्य या संघ राज्य विधान परिषद का सदस्य, और वह, अयोग्यता संघ राज्य

[illegible] के अधीन विहित प्रपत्र [illegible] निम्न प्रकार से प्रस्तुत करता है;

(iii) शीघ्र पुनर्वास, सामाजिक, सामुदायिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, कानूनी मुद्दे, सीमा मुद्दे और अन्य मुद्दे के विवरण और उक्त प्रस्ताव के कार्यों के पूर्णतया के लिए समय अनुसूचियां तथा [illegible] किया गया [illegible] प्रस्तुत करता है;

(iv) [illegible] जिन्हें संलग्न में दर्शाया गया है जो भारतीय प्रत्यायन (संघ और पारुदेश) अधिनियम, 1990 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (मोटरीय यान अधिनियम) के उपबंधों के अनुसार सूट के रूप हैं;

(v) [illegible] भूमि, अन्य सामान्य पथ, इस्तुतेश, अस्थायी [illegible], डाक और तार विभाग के आर, [illegible] सरकार और अन्य प्राधिकार के कार्यकलाप शामिल

4. विनिर्दिष्ट निम्नलिखित दर से अधिक नहीं होगा [illegible] प्रस्ताव में स्वीकृत नहीं करेगा अर्थात् :—

विवरण	विनिर्दिष्ट प्रवर्ग वाले के लिए विनिर्दिष्ट दर का प्रतिशत
(i) [illegible]	विनिर्दिष्ट प्रवर्ग वाले की दर का 25 प्रतिशत
(ii) [illegible]	विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान की दर का 10.50 प्रतिशत

परन्तु [illegible] प्रस्ताव पुनर्वास के लिए [illegible] [illegible] है, वहां विनिर्दिष्ट [illegible] प्रस्ताव में [illegible] [illegible] या [illegible] के यान [illegible] का [illegible] करता है।

5. जब कभी किसी [illegible] विनिर्दिष्ट [illegible] के विनिर्दिष्ट [illegible] के अनुसार [illegible] की जाएगी।

6. यदि किसी ऐसे [illegible] यान में कोई [illegible] [illegible] और [illegible] वर्ग की [illegible] के अधीन नहीं आते हैं।

7. विनिर्दिष्ट, इस अधिसूचना का [illegible] जिसमें [illegible] [illegible] प्रस्ताव को [illegible] भी है [illegible] से [illegible] प्रस्ताव [illegible] (विवरण में एक [illegible] [illegible] से होगा) [illegible] प्रस्ताव की [illegible] में [illegible] [illegible] विहित [illegible] और [illegible] [illegible] के द्वारा [illegible] प्रकाशित करेगा।

8. विनिर्दिष्ट यदि किसी अधिकारी का [illegible] [illegible] के [illegible] के [illegible] में [illegible] प्रस्ताव का विनिर्दिष्ट के [illegible] [illegible] करने के लिए [illegible] कि [illegible] का [illegible] [illegible] की गई दर से अधिक [illegible] [illegible] है और [illegible] का [illegible] [illegible] प्रस्तावकर्ता को और [illegible] [illegible] के लिए [illegible] [illegible] पहुंचने [illegible] [illegible] है।

10. [illegible] के [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible]

expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of said section at the rate specified in column (3) of the following Table, on the category of vehicles specified in column (2) thereof, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely :—

TABLE

The fee shall be collected at the Toll Plazas at Km. 410.140 and Km 442.800.

Sl. No.	Category of Vehicle	Rate of base fee per Km per vehicle per one way trip (in rupees)
1.	Car, Passenger Van or Jeep	0.60
2.	Light Commercial Vehicle (LCV)	0.90
3.	Truck/Bus	1.40
4.	Multi Axle Vehicle (>2 axle)	3.25
5.	Earth moving equipment and heavy construction machinery	3.00

Notes :

1. For the purposes of this notification,

(i) "actual fee" means the fees actually charged from the road users of the said section on the basis of :

(a) half of the length of the project highway;

(b) base fee given in the above Table duly indexed, and shall be rounded off to the nearest one rupee;

(ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section begins after issue of the completion certificate or the provisional completion certification as the case may be, by the [Independent Consultant] upon completion of the said section in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;

(iii) "local personal traffic" means and includes a personal vehicle (car/passenger van/jeep) which is registered with the Concessionaire by any person who normally resides or works at a place that can normally be approached only by using a part of the said section, such person is, therefore, required to use such vehicle for commuting on a part of the said section, without crossing more than one toll plaza, in the course of normal travel to and from his place of work or residence;

(iv) "local commercial traffic" means any commercial vehicle including buses, trucks, light motor vehicles or taxis engaged in carrying goods and passengers registered with the Concessionaire as plying routinely on the said section without crossing more than one toll plaza;

(v) "termination date" means the date on which the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;

(vi) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section shall have the meanings respectively assigned to them in the said Agreement.

2. The actual amount of fee and the revision thereof effective from 1st September every year shall be computed as follows.

$$\text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}} \times 50\% \text{ of the length of the said section (in Km)}$$

Where

- WPI-A = is the Wholesale Price Index on June, 1997 (131.6);
- WPI-B = is the average Wholesale Price Index available for the year ending March, 31st preceding the fee revision date.

3. When a vehicle has to cross the said section more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee for multiple trips at one and half times the rates as given in the above Table while crossing the toll plaza in the first trip itself and where a vehicle has to use the said section continuously and frequently for the entire month or even beyond that, the vehicle owner may have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times the rate applicable for single trip as specified in the aforesaid Table.

Explanation.—For the purpose of this notification "day" shall be counted as continuous period of twenty-four hours.

4. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely :—

(i) Vehicles

(A) having VIP symbols or officially belonging to :

(a) the President of India;

(b) the Vice-President of India;

(c) the Governor of a State and Lieutenant Governor of a Union Territory;

(d) a Foreign dignitary on State visit to India;

(e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;

(f) the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislative Assembly or a Minister for the Union or State or Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle;

(g) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(B) belonging to winner of gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award;

(ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made thereunder (to extended to Navy);

(iii) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.

5. Concessionaire shall not collect fees from Local Personal Traffic and Local Commercial Traffic in the excess of the following discounted rate :

(i) Local personal traffic :	Twenty-five per cent of the applicable fee for the specified category of vehicle.
(ii) Local commercial traffic :	Fifty per cent of the applicable fee for the specified category of vehicle.

Provided, that if a separate service lane is opened for free use by local traffic, the Concessionaire shall levy and collect fee from such local traffic, if they use the four lane highway.

6. As and when a service lane is constructed, the Concessionaire shall not collect any fee from the users of such lane.

7. No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle, which is not covered under the above Table.

8. The Concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provisions of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.

9. The Concessionaire shall nominate an officer as in-charge of fee collection and the Concessionaire and the said officer shall be responsible to ensure that fee is collected at not more than the agreed rate and the fee collection is smooth without causing undue hardship to the road users and for all matters connected therewith.

10. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths, also the height of the display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.

11. The actual fee to be charged from users shall be computed by the Concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible after 31st March, in every year but at least forty-five days before the revised rate is to be effective so as to enable the Authority to provide any reminders or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/4/NHAI-BOT/CO/OC Amritsar (407)-456.1) BOT]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

2324 GI/09-2